

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम० के० सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 713-एक/2001 विरुद्ध आदेश दिनांक 31-01-2011 पारित द्वारा - अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना - प्रकरण क्रमांक 148/1989-90 निगरानी

मोहम्मद इशाक पुत्र गेंदे खॉ
निवासी श्योपुर कलों तहसील एंव
जिला श्योपुर कलों म०प्र०
विरुद्ध

--आवेदक

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- 2- नगरपालिका परिषद श्योपुर कलों द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्योपुर कलों मध्यप्रदेश

----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी०के०शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 5-1-2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/1989-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-7-2010 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार श्योपुर कलों को श्योपुर कलों स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 19 एंव 93 (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया गया है) में वृक्षारोपण अनुमति हेतु आवेदन दिया। तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 13 अ-61/1987-88 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 31-5-88 से वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की। तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण करने पर अनियमिततायें किया जाना पाने से अपर कलेक्टर, श्योपुर कलों ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 112/1989-90 दर्ज किया तथा आवेदक की

Rm

[Handwritten signature]

युनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-5-1990 पारित किया तथा भूमि नगरपालिका क्षेत्र स्थित होने से तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-5-88 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 148/1989-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-7-2010 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादोक्त भूमि शासकीय अभिलेख में नगरपालिका भूमि अंकित है एवं तत्समय श्योपुर नगर एवं वर्तमान में जिला बन चुके श्योपुर कलों स्थित भूमि है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 239 में व्यवस्था दी गई है कि :-

धारा 239 - दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों में अधिकार -

1. जहां इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्राम की दखल रहित भूमि में कोई फलदार वृक्ष लगाया गया हो और वैसा अभिलिखित हो, जहां इस बात के होते हुये भी कि ऐसी भूमि राज्य सरकार में विहित है, ऐसा व्यक्ति और उसके हित उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वृक्षों के कब्जे तथा फलोपयोग के लिये किसी रायल्टी या अन्य प्रभार का भुगतान किये बिना हकदार होंगे।

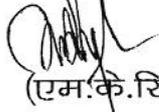
विचाराधीन प्रकरण में भूमि दखल रहित नहीं है अपितु नगर पालिका की नगरेत्तर क्षेत्र की भूमि है जिसके कारण ऐसी भूमि

for



पर वृक्षारोपण की अनुमति देने हेतु तहसीलदार सक्षम नहीं है जिसके कारण अपर कलेक्टर, श्योपुर कलों ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 112/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 22-5-1990 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-5-88 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और इन्हीं कारणों से विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 148/1989-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-7-2010 में अपर कलेक्टर श्योपुर कलों के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/1989-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-7-2010 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।



(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

for